

Vol.: 51 Issue: 101  
02/06/2026

# समाचार पत्रों से चयनित अंश NEWSPAPER CLIPPINGS

A Daily Compilation of News Related to DRDO,  
Defence, Science & Technology



Defence Science Library  
Defence Scientific Information and Documentation Centre  
Metcalfe House, Delhi -110054



## CONTENTS

S. No.	Title	Source	Page No.
<b>Defence News</b>			<b>1-9</b>
1	114 राफेल विमानों का ऑर्डर	<i>Punjab Kesari</i>	1
2	India begins process to procure 114 jets for Rs 3.25 lakh crore	<i>The Times of India</i>	1
3	डिफेंस निर्यात में भारत का दबदबा, 4 देशों से 21000 करोड़ के सौदे	<i>Punjab Kesari</i>	3
4	हिंद-प्रशांत की सुरक्षा को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ	<i>Dainik Jagran</i>	4
5	India, Australia agree to advance maritime awareness activities	<i>The Indian Express</i>	4
6	India, Oz stress on supply chain security, pledge greater def ties	<i>The Asian Age</i>	6
7	'Better military ties will be in focus when Modi and Albanese meet': Australian Defence Minister	<i>The Tribune</i>	6
8	भारत के खिलाफ नहीं होगा म्यांमार की धरती का इस्तमाल: ह्वाइंग	<i>Dainik Jagran</i>	7
9	Won't allow our territory to be used against India's interests: Myanmar	<i>The Indian Express</i>	7
10	पाक और बांग्लादेश सीमा पर लगेगी हाईटेक स्मार्ट फेंसिंग	<i>NavBharat Times</i>	9
<b>Science &amp; Technology News</b>			<b>10-12</b>
11	Skyroot flags-off Vikram-1, India's first private orbital launch soon	<i>Press Information Bureau</i>	10

# Defence News

## 114 राफेल विमानों का ऑर्डर

Source: Punjab Kesari, Dt. 02 Jun 2026

पंजाब केसरी/नई दिल्ली

भारत ने भारतीय वायु सेना की खातिर 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये

की डील के लिए फ्रांस को 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' जारी किया है। यह 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की 'एक्विजिशन विंग' द्वारा इस डील के लिए फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया था। इस डील के तहत, 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही फ्रांसीसी निर्माता 'दसाल्ट एविएशन' द्वारा भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि फ्रांसीसी पक्ष से अगले दो से तीन महीनों में भारतीय अनुरोध पत्र या टेंडर का जवाब देने की उम्मीद है, और दोनों पक्षों के अगले एक साल के भीतर बातचीत



● फ्रांस को भेजा 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट',

पूरी करके सौदा पक्का कर लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून के मध्य के आसपास फ्रांस दौरे पर जाने की उम्मीद है, और फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों के दौरान राफेल सौदे पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत अपने बेड़े में लड़ाकू विमान स्क्वाड्रनों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, और इस कमी से निपटने के लिए वह बड़ी संख्या में उन्नत 4.5-जेनरेशन-प्लस राफेल विमानों को शामिल करने के प्रयास कर रहा है जहां भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने पहले ही 62 राफेल विमानों का ऑर्डर दे दिया है।

\*

## India begins process to procure 114 jets for Rs 3.25 lakh crore

Source: The Times of India, Dt. 02 Jun 2026

India has formally begun the process of acquiring 114 Rafale fighter jets from France in a deal estimated to be worth around Rs 3.25 lakh crore, marking a major step in one of the country's largest-ever military procurement programmes.

According to defence ministry sources cited by ANI, the Acquisition Wing of the Ministry of Defence issued a Letter of Request (LoR) to the French government last week, initiating the government-to-government process for the proposed purchase. The French side is expected to respond within the next two to three months, with negotiations likely to be completed and the agreement finalised within a year, ANI reported.

The proposed acquisition forms part of the Indian Air Force's Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA) programme, which aims to address the service's declining fighter squadron strength. The IAF currently operates 36 Rafale jets procured under the 2016 India-France agreement and is facing a

significant capability gap, with its fighter strength falling to around 29 squadrons against the sanctioned requirement of 42.5.

# RAFALE

DEFENCEHQ  
—THE TIMES OF INDIA

## INDIA'S STRIKE EDGE

MAX. TAKE-OFF WEIGHT | **24.5 tonnes**  
 OVERALL EMPTY WEIGHT | **10 tonnes**  
 FERRY RANGE | **3,700 km**

SERVICE CEILING | **50,000 ft**  
 TOP SPEED | **1.8 MACH**  
 at high altitude

COMBAT RADIUS | **1,000 km**




LENGTH | **15.30 m**  
 HEIGHT | **5.30 m**  
 WING SPAN | **10.90 m**

WEAPONS SYSTEMS		
<b>AIR-TO-AIR</b>	<b>AIR-TO-SURFACE</b>	<b>PRECISION MUNITIONS</b>
<b>Meteor</b>   Ramjet-powered missile with range beyond 100 km	<b>AM39 Exocet</b>   Anti-ship missile (~70 km)	<b>Hammer</b>   Navigation-guided smart bombs
<b>MICA</b>   Infrared and radar-guided medium-range missile	<b>SCALP</b>   Long-range cruise missile (>560 km)	<b>Paveway</b>   Laser-guided bombs
ELECTRONIC WARFARE & SENSORS		
<b>SPECTRA</b>	<b>FRONT SECTOR OPTRONICS</b>	<b>RBE2-AA AESA RADAR</b>
Integrated suite with radar jamming, missile warning and infrared decoy systems	Infrared search-and-track system for passive target detection	Electronically scanned radar with range of up to 200 km for aerial targets

Under the proposed deal, the majority of the aircraft will be manufactured in India through a partnership between French aerospace company Dassault Aviation and an Indian firm under the Make in India initiative. Defence officials have indicated that around 90 to 94 aircraft could be built domestically, while the remaining jets would be supplied directly from France. The programme is expected to achieve nearly 50 per cent localisation.

The project would also mark a milestone for the Rafale programme, as it would be the first time the fighter aircraft is manufactured outside France. Officials have said the agreement will allow India to integrate indigenous weapons and systems into the aircraft while ensuring a transparent procurement process without intermediaries.

The move comes ahead of Prime Minister Narendra Modi's expected visit to France in mid-June and coincides with Indian Air Force chief Air Chief Marshal A P Singh's visit to the country, where he is expected to engage with French defence officials and Dassault facilities.

<https://timesofindia.indiatimes.com/defence/news/big-update-in-rafale-deal-india-begins-process-to-procure-114-jets-for-rs-3-25-lakh-crore/articleshow/131444796.cms>

\*

## डिफेंस निर्यात में भारत का दबदबा, 4 देशों से 21000 करोड़ के सौदे

Source: Punjab Kesari, Dt. 02 Jun 2026

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, लॉयटरिंग म्यूनिशन और 'नेत्र' जैसे स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में भारतीय 'वार' मशीनरी की मांग में भारी उछाल आया है। रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक है। भारत ने अब 2029-30 तक 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस, वियतनाम और दो अन्य देशों के साथ करीब 12,500 करोड़ के सौदे हो चुके हैं। फिलीपींस के साथ करीब 3,200 करोड़ की डील पूरी हो चुकी है। वियतनाम से रु 5,800 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने वाली है। इंडोनेशिया में लगभग रु 3,600 करोड़ की डील अंतिम चरण में है, जबकि मलेशिया और थाईलैंड ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एचएएल और अदानी डिफेंस जैसी कंपनियां अपना उत्पादन तेजी से बढ़ा रही हैं।



### ● ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों का हुआ सौदा

भारत वर्तमान में दुनिया के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, जहां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए \$2.8 अरब के भारतीय रक्षा उपकरण और कल्पुर्जे भेजे जाते हैं। साल 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 1,522 करोड़ था, जो एक दशक से भी कम समय में 25 गुना से अधिक बढ़ चुका है।

**आकाश-1एस एयर डिफेंस सिस्टम :** आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया के साथ रु 6,100 करोड़ का अनुबंध पहले ही हो चुका है और इसकी डिलीवरी वर्तमान में जारी है, जिसे हाल ही में आर्मेनिया की सालाना परेड में भी देखा गया था।

\*

## हिंद-प्रशांत की सुरक्षा को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ

Source: Dainik Jagran, Dt. 02 Jun 2026

नई दिल्ली, प्रेड: वैश्विक उथल-पुथल, पश्चिम एशिया संकट के बाद ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंताओं के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित 'रक्षा मंत्रियों के दूसरे दौर के संवाद' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गर्मजोशी दी। दोनों नेताओं ने माना कि आज दोनों देश रणनीतिक रूप से जितने करीब हैं, उतने इतिहास में कभी नहीं रहे। दोनों देशों ने सोमवार को नौवहन, हवाई पारगमन और निर्बाध समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया।



नई दिल्ली में सोमवार को गार्ड आफ आनर के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस का स्वागत करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह • एएनआइ

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करने के लिए तैयार है। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

- राजनाथ सिंह

आज हमारे संबंध इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, जो गहरे भरोसे की बुनियाद पर टिके हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है।

- रिचर्ड मार्लेस

रक्षा साजो-सामान के लिए बनेगा समझौता : इस उच्च स्तरीय बैठक का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा दोनों देशों के बीच रक्षा साजो-सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) विकसित करने का निर्णय रहा। यह कदम सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन और सह-विकास की दिशा में एक मील

का पत्थर साबित होगा। दोनों देशों ने 'ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्वोरिटी कोलाबोरेशन रोडमैप' को अंतिम रूप देने और समुद्री गश्ती विमानों के जरिये 'अंडर-सी डोमेन अवेयरनेस' (समुद्र के भीतर की निगरानी) बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा, इसी साल पहली 'ज्वाइंट स्टाफ टाक्स' शुरू करने का भी स्वागत किया गया।

'क्वाड' को मजबूती और मुक्त समुद्री व्यापार का संकल्प: बैठक में दोनों मंत्रियों ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के 'क्वाड' समूह की बढ़ती ताकत की सराहना की। साथ ही गुरुग्राम स्थित 'इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर' के माध्यम से समुद्री क्षेत्र की कमान को मजबूत करने साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई।

\*

## India, Australia agree to advance maritime awareness activities

Source: The Indian Express, Dt. 02 Jun 2026

Defence Minister Rajnath Singh and his Australian counterpart Richard Marles have agreed to advance collaborative maritime domain awareness activities using maritime patrol aircraft and to explore opportunities to enhance undersea domain awareness. The two leaders on Monday co-chaired the second edition of the India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi.

According to a joint statement issued by the two countries, the ministers welcomed the significant progress in bilateral relationship and reflected on the enhanced consultation and cooperation since the inaugural edition of the dialogue on October 9 last year. The joint statement noted that the two sides discussed efforts to finalise the Joint Maritime Security Collaboration Roadmap.

"They agreed to progress the collaborative maritime domain awareness activities by maritime patrol aircraft and explore opportunities to enhance undersea domain awareness," it said, adding that they also encouraged further cooperation between the Indian Coast Guard and Australia's Maritime Border Command.

Marles also met External Affairs Minister S Jaishankar on Monday. After the Meet, Jaishankar posted on X: "A pleasure to meet Deputy Prime Minister & Defence Minister Richard Marles of Australia today. Shared assessments on regional developments, Indo Pacific and further advancement of our Comprehensive Strategic Partnership."

India-Australia relations gained significant momentum following PM Narendra Modi's visit to Australia in 2014. The relationship has since produced several key security agreements, including

the Comprehensive Strategic Partnership and the Mutual Logistics Support Agreement (MLSA). Singh and Marles, during the meet, affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific.

“They underscored the importance of freedom of navigation and overflight, and their strong support for unimpeded trade in the region & other lawful uses of the sea consistent with international law, particularly the 1982 United Nations convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” the statement noted.

The statement further said India and Australia, as co-leads of the Indian Ocean Rim Association Working Group on Maritime Safety and Security, look forward to jointly host a Search & Rescue and tabletop exercise at Maritime Rescue Coordination Centre, Chennai this month to strengthen maritime safety and security cooperation in the Indian Ocean Region.

“The two sides undertook to explore arrangements to enhance procedural interoperability for exercises and operations, building on the 2020 Mutual Logistics Support Arrangement,” it said, adding that they also agreed to continue aircraft deployment from each other’s territories to build operational familiarity. The ministers announced that India and Australia would begin developing a Memorandum of Understanding regarding the Provision of Defence Articles and Defence Services as the next step in deepening defence industrial collaboration. The two sides agreed to explore further exchanges, including through the Joint Working Group on Defence Industry, Research and Materiel.

The Ministers are keen on exploring future defence science and technology research cooperation in new technology areas like sensor technologies,” the statement. The Australian Deputy Prime Minister invited India to participate in the 2026 Australian Defence Science, Technology and Research Summit.

Both sides also discussed the growing engagement between their defence forces, including in the upcoming Exercise Talisman Sabre 2027, Australia’s participation in India’s Exercise Milan and Australia’s Exercise Kakadu in February and March this year.

“They looked forward to their countries’ participation in each other’s multinational air exercises in 2026, including operationalising the bilateral Implementing Arrangement on Air-to-Air Refuelling at Exercise Pitch Black,” the statement said. It added that the two sides noted with satisfaction the expansion of military cooperation into new areas.

“They welcomed the evolution of Army Exercise Austrahind this year to focus on amphibious combat and littoral manoeuvres. Australia welcomed India’s inaugural participation in Operation Render Safe 2026,” the statement said, adding that India welcomed Australia’s invitation for participation in submarine rescue exercise Black Carillon.

The Ministers welcomed increased information sharing between operational headquarters and said they are looking forward to the inaugural Joint Staff Talks later this year, the statement said. The two leaders encouraged their officials to finalise arrangements for the deployment of an Indian visiting instructor at the Australian Defence College in 2028-2029 to strengthen professional military engagement, knowledge exchange, and strategic alignment.

<https://indianexpress.com/article/india/india-australia-defence-maritime-cooperation-dialogue-rajnath-singh-10719203/>

\*

# India, Oz stress on supply chain security, pledge greater def ties

Source: *The Asian Age*, Dt. 02 Jun 2026

AGE CORRESPONDENT  
NEW DELHI, JUNE 1

Defence minister Rajnath Singh and his Australian counterpart Richard Marles on Monday held the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue where both countries underscored the importance of freedom of navigation, overflight and unimpeded maritime trade amid disruptions in energy supply chains following the West Asia crisis as well as concerns over China's increasing assertiveness in the Indo-Pacific.

India and Australia vowed to enhance collaboration on maritime domain awareness to increase interoperability among the partners. The ministers expressed strong support for the Quad Indo-Pacific Maritime



Defence minister Rajnath Singh with Australian deputy prime minister Richard Marles along with CDS Lt. Gen. N.S. Raja Subramani, Army Chief Gen. Upendra Dwivedi and Navy Chief Adm. Krishna Swaminathan in New Delhi on Monday.

— PTI

Surveillance Collaboration initiative to be implemented initially in the Indian Ocean Region.

The two sides discussed advancements in bilateral maritime security cooper-

ation and efforts to finalise the Joint Maritime Security Collaboration Roadmap.

They agreed to progress the collaborative maritime domain awareness activi-

ties by maritime patrol aircraft and explore opportunities to enhance undersea domain awareness. They also encouraged further cooperation between the Indian Coast Guard and Australia's Maritime Border Command.

The Ministers affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific.

They underscored the importance of freedom of navigation and overflight, and their strong support for unimpeded trade in the region and other lawful uses of the sea consistent with international law, particularly the 1982 United Nations convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

\*

## 'Better military ties will be in focus when Modi and Albanese meet': Australian Defence Minister

Source: *The Tribune*, Dt. 02 Jun 2026

Improving India-Australia military ties, including those connecting the defence industry, will be a key part of discussions when Prime Minister Narendra Modi and Australian PM Anthony Albanese meet for the annual leaders' summit. Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles gave out the expected focus of the talks that are likely in the next couple of months. Marles, who is in India for the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue, was speaking to a select group of media persons after the dialogue he had with Defence Minister Rajnath Singh here in New Delhi.

"Defence will be a key part of the discussions that our Prime Ministers undertake, because in their previous summits, defence has been very central," said Marles. The two PM's have directed us as Defence Ministers to work in respect of the defence relationship. "We are near to finalisation of a renewal and strengthening of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation", Marles added. There has been significant progress on the Joint Maritime Security Collaboration Roadmap, and that is important in the context of the upcoming Prime Ministerial Summit. Australia values its defence relationship with India. "It is going from strength to strength," the visiting minister said. Australia and India have discussed establishing an information-sharing agreement and we've

now seen really significant cooperation from our respective defence intelligence organisations over the last six months.

The defence industry is absolutely a key part of the conversation that we had today. "There has been really significant progress in respect of the defence industry in relation to our two countries," Marles said. The two sides are looking at a range of options to increase cooperation and integration of their respective supply chains. "Actually, we come out of today's meeting with a much greater sense of optimism about what we can do... It benefits in terms of the Australian industry being able to supply here, but it very much sees benefits in terms of utilising the Indian supply chain, using the Indian defence industry to help contribute to our capability as well," the minister said.

<https://www.tribuneindia.com/news/india/better-military-ties-will-be-in-focus-when-modi-and-albanese-meet-australian-defence-minister/>

\*

## भारत के खिलाफ नहीं होगा म्यांमार की धरती का इस्तमाल: ह्लाइंग

Source: Dainik Jagran, Dt. 02 Jun 2026

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: चीन के समर्थक माने जाने वाले म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि म्यांमार की धरती का इस्तमाल कभी भी भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ म्यांमार की 1,640 किमी लंबी सीमा लगती है। म्यांमार की अस्थिरता और वहां चीन का बढ़ता प्रभुत्व चिंता का विषय रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में मोदी व ह्लाइंग के बीच हुई बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में व्यापार एवं आर्थिक संबंध, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहायता तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर बल दिया।

म्यांमार में फरवरी 2021 के



नई दिल्ली में सोमवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी • एएनआइ

सैन्य तख्तापलट और लंबे संघर्ष के बाद, अप्रैल, 2026 में हुए संसदीय चुनावों के जरिये राष्ट्रपति ह्लाइंग ने सत्ता संभाली है। हालांकि, इस देश की आंतरिक स्थिति में सुधार की संभावना बहुत कम है। एक तरफ

- ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की
- मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की प्रतीक आंग सान सू की एवं लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा भी उठाया

म्यांमार की सेना है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वाले दल एवं चिन ब्रदरहुड और आराकान आर्मी जैसी विद्रोही सेना है। रखाइन प्रांत के अधिकांश हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। साथ ही,

चीन का वर्चस्व भी म्यांमार की सरकार पर बढ़ता जा रहा है।

मोदी और ह्लाइंग के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा (रुपया-क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म) के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। म्यांमार, चीन के साथ पहले से ही इस तरह की व्यवस्था कर चुका है। भारत एवं म्यांमार के बीच दो अरब डालर का कारोबार होता है। मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की प्रतीक और घर में नजरबंद आंग सान सू की का मुद्दा भी उठाया और भारत की यह इच्छा दोहराई कि म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए।

\*

## Won't allow our territory to be used against India's interests: Myanmar

Source: The Indian Express, Dt. 02 Jun 2026

Myanmar President U Min Aung Hlaing assured Prime Minister Narendra Modi on Monday that Myanmar's territory "would not be permitted to be used against India's security interests". In the past, India has repeatedly expressed concern over Northeast insurgent groups operating from within Myanmar. Briefing reporters after the bilateral meeting, Foreign Secretary Vikram Misri underlined that "stability and peace in Myanmar is a major interest for India". Min Aung Hlaing is

visiting India from May 30 to June 3 — his first visit since taking over as President. The former chief of the military junta government was elected President on April 3, five years after he grabbed power in a coup, ousting an elected government. Misri said the leaders discussed cooperation on defence and security, critical minerals and rare earth, and connectivity projects.

Modi also raised the issue of Nobel laureate Aung San Suu Kyi, who is in detention in Myanmar since the military coup in 2021. “The Prime Minister reaffirmed India’s support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. The President of Myanmar, in particular, reiterated the assurance that Myanmar’s territory would not be permitted to be used against India’s security interests,” Misri said.

“The aspect of internal security is obviously the effort by the Myanmar State to bring all the ethnic armed organisations and groups onto a single platform to advance the peace process... this is something in which we obviously have an interest, because stability and peace in Myanmar is a major interest for India, not just for the security of the Northeast and the safety and security of people living along the 1,643-km-long border that we have with them, but also for our interests, such as connectivity to Southeast Asia,” Misri said.

“Security and stability in Myanmar is also important for the coherence of ASEAN as a whole, because Myanmar is an important and large country within the ASEAN framework,” he said, outlining the regional dimension. “Apart from that, there is the very important question of the activities of Indian insurgent groups in Myanmar close to our borders, and this is something that the Prime Minister raised with the President. The President once again reiterated his assurance that Myanmar was sensitive to these concerns, and would do everything necessary to ensure that there was action on these, and these don’t become a cause of threat against the security of India,” he said.

Responding to questions on Suu Kyi, Misri said: “The Prime Minister did raise this matter with the President, and this was a discussion that was largely in the context of the peace process... in the context of the points that the Prime Minister was making on the need for... inclusion, the need to have all stakeholders at the table and to examine the points of views of all the interlocutors who have been part of this process... it was a bit of a freewheeling discussion on that issue, and that is where issues related to democracy were also raised.”

Underlining that the engagement with Myanmar is “not intended to be a commentary on its internal political arrangements”, Misri said: “We have always proceeded on the principle that sustained dialogue is what is important and... an imperative for India as a neighbour... the answer is clearly not disengagement... So we have consistently engaged, and while engaging, we have always put forward our thoughts on all of these issues related to democracy, the peace process, inclusion, and the absolute importance of having all stakeholders as part of the dialogue at the table.”

“We have always believed that eventually the difficulties that face Myanmar will have to be sorted out by the people of Myanmar talking among themselves. This will have to be a Myanmar-led solution and a Myanmar-owned solution,” he said. On defence cooperation, Misri said the focus is on “training”, “capacity building”, institution building, and UN peacekeeping. “...we have a 1,643-km-long border. There are important defence and security related interests in the context of that border, and that is also something that gets discussed when various mechanisms related to defence cooperation get together,” he said. Misri also said that over the last year-and-a-half, over 2,400 Indian citizens have been repatriated from cyber scam compounds within Myanmar. “As of now, we have over 150-odd Indian citizens that we know of... who are still stuck in some of these

cyber scam compounds... we are in touch with the Myanmar government to try and repatriate them as well," he said.

On the two major connectivity-related projects — the Kaladan multimodal transit transport project and India-Myanmar-Thailand trilateral highway project — Misri said: "These projects have been underway for several years, and they have been delayed... Right now, the obstacle that faces both these projects is the security situation in Myanmar. The Kaladan highway is in an area where there are active hostilities going on between the Myanmar Army and ethnic armies in Rakhine state; the section of the trilateral highway where work was underway is in an area where ethnic armed groups are quite active... Nevertheless, we have continued to engage with the Myanmar authorities, and wherever there has been a possibility to take forward the work by utilising either lulls in fighting or by making sure that the security of the workers is not going to be impacted, we have been able to move forward, but this is something that that remains a major priority. It was raised by the Prime Minister today, and the President once again gave his assurance that Myanmar would do everything to ensure these projects move forward towards completion," he said.

Modi also conveyed that the Mekong Ganga ICCR scholarships for Myanmar students would be enhanced from 36 to 100 from 2026. The Myanmar President, who arrived in Delhi on Saturday after visiting Bodh Gaya, also met President Droupadi Murmu, External Affairs Minister S Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval. He will head to Mumbai on Tuesday.

<https://indianexpress.com/article/india/wont-allow-our-territory-to-be-used-against-indias-interests-myanmar-10719151/>

\*

## पाक और बांग्लादेश सीमा पर लगोगी हाईटेक स्मार्ट फेंसिंग

Source: NavBharat Times, Dt. 02 Jun 2026

**Maneesh.Aggarwal**  
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए नई डिजाइन की स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में इसका जिक्र किया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह फेंसिंग कुछ संवेदनशील इलाकों में लगाई भी जा चुकी है और वहां घुसपैठ, तस्करी तथा पशु चोरी की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक, यह नई फेंसिंग एंटी कट और एंटी क्लाइंब तकनीक पर आधारित है। करीब 12 फीट ऊंची इस बाड़ को काटना या उस पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। पुरानी डबल और ट्रिपल लेयर फेंसिंग की तुलना में इसकी सिंगल लेयर डिजाइन ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। जालियों के बीच इतना कम गैप

**क्या है खासियत**

नई स्मार्ट फेंसिंग में सेंसर, थर्मल कैमरे, AI तकनीक और अलार्म सिस्टम एक साथ काम करेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, सुरंग खोदने या बाड़ काटने की कोशिश पर कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल जाएगी। AI कैमरे इंसानों और जानवरों में अंतर पहचान सकेंगे। लेजर वॉल का भी परीक्षण हो रहा है, जिससे बिना छुए निगरानी संभव होगी।

रखा गया है कि उंगली तक बाहर नहीं निकाली जा सकती। फेंसिंग के नीचे सुरंग खोदने से रोकने के लिए इसकी फाउंडेशन भी विशेष तरीके से तैयार की गई है। इसमें सेंसर और अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं, जो किसी भी छेड़छाड़ या खुदाई की कोशिश पर तुरंत BSF कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। संवेदनशील इलाकों में थर्मल कैमरे और AI आधारित निगरानी सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

\*

# Science & Technology News

## Dr Jitendra Singh says, "Anusandhan National Research Foundation" (ANRF) is democratising research funding, launches ₹200-crore MAHA Water Mission to support StartUps

*Source: Press Information Bureau, Dt. 01 Jun 2026*

Launching the ₹200-crore "Anusandhan National Research Foundation (ANRF) –Ministry of Jal Shakti MAHA Water Mission to support StartUps in the Water sector, Union Minister of State (Independent Charge) for Science & Technology, Earth Sciences and Minister of State for PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today said that the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) is democratising research funding by expanding opportunities for StartUps, MSMEs, universities and innovators across the country, ensuring that national missions, scientific resources and innovation support are no longer confined to a limited number of institutions.

Addressing the inaugural session of the National Workshop on R&D in Water at Dr Ambedkar International Centre, New Delhi, Dr Jitendra Singh said ANRF was created to address a long-standing concern that a significant share of research funding often flowed to a few established institutions, while smaller universities, startups and emerging innovators remained outside the mainstream innovation ecosystem. The Foundation, he said, is widening access to resources, partnerships and mission-oriented research opportunities, enabling institutions and innovators from across the country to contribute to national priorities.

The Minister said ANRF has emerged as a national platform for mission-driven innovation and has already launched Missions for Advancement in High-Impact Areas (MAHA) in strategic sectors including Electric Vehicles, Drones, Medical Technologies, 6G Communications and Water. These missions are creating an integrated pathway from fundamental research to technology development, validation and deployment while bringing together academia, industry, startups and government institutions to solve critical national challenges. The launch of the MAHA Water Mission, he said, marks another major step in this direction.

Dr Jitendra Singh said the mission reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of leveraging science, technology and innovation to address developmental priorities. He said that the Prime Minister had, for the first time, brought water-related functions under a unified framework through the creation of the Ministry of Jal Shakti, elevating water security to a national priority. The MAHA Water Mission, he said, seeks to build on that vision by creating a collaborative platform that connects scientific institutions, industry, startups and grassroots stakeholders to develop scalable and sustainable solutions for the water sector.

Highlighting India's expanding innovation ecosystem, Dr Jitendra Singh said the country has progressed from about 350–400 startups a decade ago to more than two lakh startups today, generating nearly 20–24 lakh jobs. He said India's startup movement has become one of the strongest drivers of innovation-led growth and programmes such as the MAHA Missions are

intended to ensure that entrepreneurial talent is channelled towards solving national challenges while creating new opportunities for employment, research and technology development.

The Minister said the Government's Whole-of-Government approach has transformed the manner in which national missions are conceived and implemented. Referring to the space sector, he said reforms introduced under Prime Minister Modi's leadership opened the sector to wider participation and created new opportunities for innovators and private enterprise. India's space economy, which remained limited in scale for decades, is today valued at nearly USD 9 billion and is expected to grow to about USD 40–45 billion in the coming years, demonstrating the power of collaborative innovation and policy support.

Dr Jitendra Singh said India's space programme has generated significant societal benefits through applications in governance, infrastructure planning, agriculture, resource mapping and public service delivery. He cited initiatives such as SVAMITVA and PM GatiShakti as examples of how space technology is contributing directly to developmental outcomes. He said similar convergence of science and technology is now being harnessed to strengthen water security and resource management.

Referring to the signing of an MoU between the Ministry of Jal Shakti and the Department of Space/ISRO, the Minister said satellite technologies, geospatial applications and scientific data are increasingly contributing to water resource mapping, groundwater assessment, irrigation planning and infrastructure development. He added that future collaborations involving Earth Sciences, Biotechnology, CSIR laboratories and other scientific institutions would further strengthen India's ability to address water-related challenges through technology-driven solutions.

During the programme, Dr Jitendra Singh and Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil jointly launched the ANRF–MoJS MAHA Water Mission, released the mission flyer and announced an open call for proposals. An Open Call for Startups and MSMEs for Product and Prototype Development was also launched during the inaugural session. The event additionally witnessed the signing of an MoU between the Department of Water Resources and the Department of Space/ISRO, besides the launch of the Jal Sanchay Jan Bhagidari, Citizen Tracking and Reporting (JSJB-CTR) Portal and App.

The MAHA Water Mission has been conceived as a national platform to accelerate innovation in the water sector by connecting science, entrepreneurship, industry, academia and grassroots action. With a projected outlay of ₹200 crore over five years, jointly contributed by ANRF and the Ministry of Jal Shakti, the programme will support multidisciplinary consortia involving universities, national laboratories, research organisations, startups, MSMEs and industry partners. Up to ₹20 crore support will be available for selected consortia to undertake technology development, field assessment, validation and deployment of high-impact solutions in the water sector.

The mission will focus on five priority themes, Water Resource Assessment and Sustainable Management, Drinking Water, Water Quality and Ecological Health, Water Use Efficiency and Circular Economy, and Climate Resilience and Adaptation. It aims to support innovations from laboratory research to field deployment while generating scalable and localised solutions for strengthening India's long-term water security.

Dr Jitendra Singh also referred to the Government's broader Research, Development and Innovation (RDI) framework, saying it would provide an additional pathway for technologies emerging from mission programmes such as MAHA Water to progress towards commercialisation and large-scale deployment. He encouraged startups, researchers, innovators and institutions to

actively participate in the opportunities being created through ANRF and contribute to building indigenous solutions for national priorities.

Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil said water security is fundamental to India's developmental aspirations and called for greater integration of research, innovation and public participation in water management. He welcomed the partnership between the Ministry of Jal Shakti and ANRF and expressed confidence that the MAHA Water Mission would help generate practical and scalable solutions for the country's water sector. Shri Patil also highlighted the growing success of the Jal Sanchay Jan Bhagidari campaign and emphasised the role of citizen participation in water conservation efforts.

The National Workshop brought together senior policymakers, scientists, researchers, startups, MSMEs, industry representatives and officials from State Water Resources Departments. Among those present were Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil; Ministers of State for Jal Shakti Dr Raj Bhushan Choudhary; Secretary, Department of Space and Chairman, ISRO Dr V. Narayanan; Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Shri V.L. Kantha Rao; Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation Shri Ashok K.K. Meena; senior officials of ANRF, researchers, innovators and representatives from academia and industry. The workshop also featured presentations on completed R&D studies and emerging technologies in water resource management, groundwater sustainability, climate resilience and water quality

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2267551&reg=3&lang=1>

\*

The Tribune  
The Statesman  
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਨਸੱਤਾ  
The Hindu  
The Economic Times  
Press Information Bureau  
The Indian Express  
The Times of India  
Hindustan Times  
नवभारत टाइम्स  
दैनिक जागरण  
The Asian Age  
The Pioneer